



2026:AHC:165735

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26618 वर्ष 2026

महेश पाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : दिव्यकांत मिश्रा, सतीश कुमार पांडे
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार पांडेय एवं श्री दिव्यकांत मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 150 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 69, 351(2) के अंतर्गत, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर में पंजीकृत मामले में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराओं 180 एवं 183 के अंतर्गत अभिलिखित पीड़िता के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता बालिग महिला है तथा पीड़िता की चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने का समर्थन नहीं करती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 13.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक द्वारा कथित रूप से, तथापि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में पीड़िता ने आवेदक द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, जबकि धारा 183 के अंतर्गत दिए गए अपने कथन में उसने कहा है कि आवेदक ने विवाह का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। पीड़िता बालिग महिला है तथा पीड़िता की चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण रिपोर्ट उसके साथ बलात्कार किए जाने का समर्थन नहीं करती है। आवेदक दिनांक 13.5.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही *कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा *माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक- **महेश पाल**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

7 अगस्त, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिषेक

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।